NITIN SIR CLASSES

THE HINDU
INDIA'S NATIONAL NEWSPAPER SINCE 1878

Daily News Analysis

The Hindu Important News Articles & Editorial For UPSC CSE

Monday, 15 Sep, 2025

Edition : International Table of Contents

Page 01 Syllabus : GS 2 : Indian Polity / Prelims	लंबित मामलों की संख्या सर्वोच्च न्यायालय को परेशान कर रही है, क्योंकि लंबित मामले 88,417 के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुँच गए हैं।
Page 06 Syllabus : GS 3 : Environment and Ecology / Prelims	प्रधानमंत्री ने भारत के पहले बांस-आधारित इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया।
Page 06 Syllabus : GS 3 : Indian Economy / Prelims	भारत को खाद्य उत्पादन के विविधीकरण में तेज़ी लाने के लिए और अधिक निवेश करना चाहिए: एफएओ के मुख्य अर्थशास्त्री मैक्सिमो कुलेन।
Page 09 Syllabus : GS 2 : Social Justice / Prelims	वैश्विक शिक्षा को घर-घर पहुँचाना।
Page 10 Syllabus : GS 3 : Science and Technology / Prelims	डीएनए पर सर्वोच्च न्यायालय के दिशानिर्देश क्या कहते हैं?
Page 08 : Editorial Analysis Syllabus : GS 2 : International Relations	एक अनियंत्रित दुनिया में भारत की स्थिति

Page 01 : GS 2 : Indian Polity / Prelims

सर्वोच्च न्यायालय में लंबित मामलों की संख्या 88,417 (सितंबर 2025) के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुँच गई है, जबकि न्यायालय 34 न्यायाधीशों की अपनी पूर्ण स्वीकृत न्यायिक क्षमता पर कार्य कर रहा है। यह भारत की न्यायिक प्रणाली में एक संरचनात्मक समस्या को उजागर करता है जहाँ लंबित मामले और विलंब एक आम समस्या बन गए हैं, जिससे न्याय तक पहुँच और न्यायपालिका की दक्षता को लेकर चिंताएँ बढ़ रही हैं।

Case pendency continues to plague the SC as backlog hits all-time high of 88,417

Krishnadas Rajagopal
NEW DELHI

The pendency of cases in the Supreme Court has reached an all-time high of 88,417, even when the court is currently functioning with its full sanctioned judicial strength of 34 judges.

The court has 69,553 civil cases and 18,864 criminal matters pending currently, the National Judicial Data Grid shows. The filing of fresh cases in August surpassed the disposal rate. A total of 7,080 cases were instituted in the court in August. The court has managed a disposal rate of 5,667 cases in the month, that is, 80.04% of the cases filed. The escalation in pendency is despite Chief Justice B.R. Gavai's decision to have more Benches working through the long summer recess of the court in a bid to decrease the case log.

Working on holidays

The CJI had renamed the summer holidays from May 23 to July "partial working days". The CJI and five senior-most judges of the court had presided over the first batch of Benches hearing cases during the summer recess. A total of 21 Benches sat in batches throughout the "partial working days", hearing and disposing of cases, till the court reopened in July.

In 2025, 52,630 cases were filed while 46,309, nearly 88%, were disposed of during a year which has already seen two Chief Justices of India with a third, Justice Surya Kant, expected to be sworn in in late November. The corresponding period in 2024 had seen a similar climb in pendency to a then peak of over 82,000 cases. The increase in pendency persists despite successive Chief Justices, from Justice D.Y. Chandrachud to Justice Gavai, taking care to maintain judicial vacancy in the top court to a minimum, if not zero.

The unceasing increase in backlog has become a perennial phenomenon since the pandemic years, and especially since 2023. The pendency had continued to rise steadily despite Justice Chandrachud, when he was CJI, acting swiftly to fill vacancies in the top court. His successors to the top judge post, Justices Sanjiv Khanna and Gavai, have spearheaded their own collegiums to promptly recommend names of judges to the government.

Past Chief Justices and even collegium resolutions have raised the issue of "huge workload".

A November 2023 collegium resolution had mentioned the bare truth that the court cannot afford even one vacancy, taking into account the "ever mounting pendency of cases". "The workload of judges has increased considerably. Bearing in mind the above, it has become necessary to ensure that the court has full working judge-strength leaving no vacancy at any point of time," the collegium had underscored.

The recent months have seen the government approve collegium recommendations for appointment to the Supreme Court without delay, often within 48 hours. Yet, the backlog continues to rise steadily.

The escalation is despite decision to have more Benches working during the SC's summer recess

समसामयिक संदर्भ

- लंबित मामलों का आँकड़ा (सितंबर 2025): 69,553 दीवानी + 18,864 आपराधिक मामले लंबित हैं।
- दाखिल बनाम निपटान (अगस्त 2025): 7,080 मामले दायर बनाम 5,667 निपटाए गए → निपटान दर 80.04%।
- वार्षिक प्रवृत्ति (2025): 52,630 मामले दायर; 46,309 निपटाए गए (~88%)।
- ऐतिहासिक प्रवृत्ति: 2024 में लंबित मामलों की संख्या 82,000 तक पहुँच गई; महामारी के वर्षों से लगातार बढ़ रही है।

- **प्रशासनिक प्रयास:**
  o मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई ने ग्रीष्मकालीन अवकाश (मई-जुलाई 2025) को "आंशिक कार्य दिवसों" में बदल दिया → 21 पीठें कार्यरत रहीं।
  o सरकार ने कॉलेजियम की सिफारिशों को 48 घंटों के भीतर मंजूरी दे दी (अतीत में देरी के विपरीत)।
- फिर भी: लंबित मामलों में वृद्धि जारी है, जो मामलों के आने और जाने के बीच प्रणालीगत बेमेल को दर्शाता है।

स्थैतिक आयाम: भारत में न्यायिक लंबित मामले

- अनुच्छेद 21 (शीघ्र सुनवाई का अधिकार): लंबे समय तक लंबित मामले मौलिक अधिकारों को कमजोर करते हैं।
- अनुच्छेद 32 और 136: सर्वोच्च न्यायालय संविधान का संरक्षक और अंतिम अपीलीय प्राधिकारी है → कार्यभार स्वाभाविक रूप से अधिक है।

- न्यायाधीश-जनसंख्या अनुपात: भारत में प्रति दस लाख न्यायाधीशों की संख्या लगभग 21 है (उच्च न्यायालय+उच्च न्यायालय+अधीनस्थ) बनाम अमेरिका में लगभग 107, ब्रिटेन में लगभग 51।
- लंबित मामलों के कारण:
  o मुकदमेबाजी की बढ़ती संस्कृति।
  o सर्वोच्च न्यायालय द्वारा केवल संवैधानिक मामलों पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय नियमित अपीलों पर विचार करना।
  o प्रक्रियात्मक स्थगन, बार-बार जनहित याचिकाएँ।
  o पूर्ण पैमाने पर प्रौद्योगिकी अपनाने का अभाव।
  o निचली न्यायपालिका में न्यायाधीशों की कमी लंबित मामलों को बढ़ा रही है।

चुनौतियाँ

1. संस्था और निपटान के बीच बेमेल - हर साल निपटाए जाने वाले मामलों की तुलना में अधिक मामले दायर किए जाते हैं।
2. संरचनात्मक अधिभार - सर्वोच्च न्यायालय संवैधानिक न्यायालय और अपीलीय न्यायालय दोनों के रूप में कार्य करता है।
3. प्रशासनिक अक्षमता - आंशिक सुधारों के बावजूद लंबी छुट्टियाँ।
4. संसाधन सीमाएँ - न्यायालय कक्ष, बुनियादी ढाँचा और अनुसंधान सहायता कर्मचारी अपर्याप्त।
5. सामाजिक-आर्थिक लागत - देरी न्यायपालिका में विश्वास को कम करती है, व्यावसायिक माहौल को प्रभावित करती है और आम नागरिकों को समय पर न्याय से वंचित करती है।

सुधार और आगे की राह

- संवैधानिक न्यायालय मॉडल: सर्वोच्च न्यायालय को संवैधानिक मामलों तक सीमित रखें; नियमित अपीलों के लिए एक राष्ट्रीय अपील न्यायालय स्थापित करें (विधि आयोग और विभिन्न विशेषज्ञ समितियों द्वारा अनुशंसित)।
- प्रौद्योगिकी अपनाना: एआई-सक्षम केस प्रबंधन, ई-फाइलिंग, डिजिटल अदालतें, "वर्चुअल बेंच"।
- प्रक्रिया सुधार: स्थगन कम करें, जनहित याचिकाओं की सुनवाई को सुव्यवस्थित करें, केस प्रबंधन के सख्त नियम।
- न्यायिक क्षमता निर्माण: निचली न्यायपालिका में स्वीकृत संख्या बढ़ाएँ; विशेष बेंच बनाएँ।
- एडीआर तंत्र: मध्यस्थता, पंचाट, लोक अदालतें ताकि आमद कम हो।
- संतुलित अवकाश: रोटेशन प्रणाली के साथ अवकाश के दौरान आंशिक रूप से काम करना जारी रखें।

निष्कर्ष

- पूर्ण न्यायिक क्षमता, त्वरित नियुक्तियों और आंशिक कार्य अवकाशों के बावजूद सर्वोच्च न्यायालय में लंबित मामलों की संख्या का रिकॉर्ड यह दर्शाता है कि भारत का न्यायिक लंबित मामला केवल रिक्तियों

का नहीं, बल्कि व्यवस्थागत ढाँचे का भी है। जब तक भारत सर्वोच्च न्यायालय की भूमिका की पुनर्कल्पना नहीं करता, निचली अदालतों को मज़बूत नहीं करता और तकनीक-संचालित सुधारों को नहीं अपनाता, तब तक "न्याय में देरी न्याय से वंचित होने के समान है" का सिद्धांत एक जीवंत वास्तविकता बना रहेगा। चुनौती केवल प्रशासनिक ही नहीं, बल्कि संवैधानिक भी है - यह सुनिश्चित करना कि सर्वोच्च न्यायालय सभी नागरिकों के अधिकारों और न्याय का सच्चा संरक्षक बना रहे।

UPSC Prelims Practice Question

प्रश्न: भारत के सर्वोच्च न्यायालय में लंबित मामलों के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. सर्वोच्च न्यायालय में स्वीकृत न्यायिक क्षमता भारत के मुख्य न्यायाधीश सहित **34** न्यायाधीशों की है।

2. अगस्त **2025** में**,** सर्वोच्च न्यायालय में मामलों के निपटारे की दर, दाखिल होने की दर से अधिक थी।

3. भारत में न्यायाधीश-जनसंख्या अनुपात**,** संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्रिटेन की तुलना में काफी कम है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं**?**

a) केवल **1** और **2**

b) केवल **1** और **3**

c) केवल **2** और **3**

d) 1, 2 और **3**

उत्तर: (**b)**

UPSC Mains Practice Question

प्रश्न: भारत का सर्वोच्च न्यायालय अपनी पूर्ण स्वीकृत क्षमता के साथ कार्यरत होने के बावजूद**,** लंबित मामलों की बढ़ती संख्या से जूझ रहा है। इस बढ़ते लंबित मामलों के कारणों का विश्लेषण कीजिए और इस चुनौती से निपटने के लिए सुधार सुझाइए। **(250 Words)**

Page 06 : GS 3 : Environment and Ecology / Prelims

असम के गोलाघाट में दुनिया के पहले हरित बांस बायोएथेनॉल संयंत्र के उद्घाटन से भारत की ऊर्जा आत्मनिर्भरता (ऊर्जा में आत्मनिर्भरता) की खोज को एक बड़ा बढ़ावा मिला है। यह भारत की स्वच्छ ऊर्जा प्रतिबद्धताओं, इथेनॉल मिश्रण लक्ष्यों और विकसित भारत 2047 के व्यापक दृष्टिकोण के अनुरूप है।

PM inaugurates India's first bamboo-based ethanol plant

Golaghat facility billed as world's first green bamboo bioethanol plant; ₹7,230-crore polypropylene project also initiated at Numaligarh Refinery; the facility aims to reduce dependence on fossil fuels

The Hindu Bureau
GUWAHATI

Clean energy: Prime Minister Narendra Modi during the inauguration of Assam Bio-Ethanol Private Ltd. (ABEL), Numaligarh Refinery Plant, in Golaghat on Sunday. PTI

Prime Minister Narendra Modi on Sunday underscored the need for India to be self-sufficient in energy. He was speaking after inaugurating the country's first bamboo-based ethanol plant in eastern Assam's Golaghat district.

He laid the foundation stone for a ₹7,230-crore polypropylene plant at the Numaligarh Refinery. The project will be established near the ₹5,000-crore bioethanol plant, a "zero-waste" facility described as the world's first to produce ethanol from green bamboo.

Terming the bioethanol plant a step toward ensuring energy security, Mr. Modi said the facility aimed to promote clean energy and reduce dependence on fossil fuels.

"Assam is a land that supports India's energy efficiency. The petroleum products from Assam are accelerating the development of India. The BJP government is trying to take this capacity of Assam to a new level," he said at a public event.

"India is one of the fastest-growing economies in the world now. Our energy needs have been increasing with our Viksit Bharat dream. We spend crores of rupees on imports as we are dependent on other countries for energy. We want to change this by trying to achieve self-sufficiency in energy," the Prime Minister said.

Deep-water exploration

"While we are focusing on hydrocarbon exploration, we are also laying stress on green energy like solar," he said, highlighting the country's national deep-water exploration mission to look for hydrocarbons under the sea. Referring to the bioethanol plant, Mr. Modi said it would benefit local farmers and tribal communities.

"The government will help them grow and procure the products to ensure a win-win situation," he said. He criticised the erstwhile Congress governments for penalising people for cutting bamboo, which was earlier categorised as a tree. He said the BJP government removed the ban on bamboo cutting and stressed that the decision was helping the locals in this part of the country.

Numaligarh Refinery Limited (NRL) officials said five lakh tonnes of green bamboo would be sourced yearly from four northeastern States, including Arunachal Pradesh and Assam, to produce 48,900 tonnes of ethanol, 11,000 tonnes of acetic acid, 19,000 tonnes of furfural, and 31,000 tonnes of food-grade liquid carbon dioxide. A joint venture of NRL and Finland's Fortum and Chempolis OY, the plant is expected to give a ₹200-crore boost to Assam's rural economy.

समसामयिक संदर्भ

- परियोजना विवरण: असम बायो-एथेनॉल प्राइवेट लिमिटेड (ABEL), गोलाघाट स्थित नुमालीगढ़ रिफाइनरी में स्थापित।
- पैमाना: ₹5,000 करोड़ का निवेश; ₹7,230 करोड़ की अतिरिक्त पॉलीप्रोपाइलीन परियोजना शुरू।
- उत्पादन क्षमता: प्रतिवर्ष 48,900 टन इथेनॉल, 11,000 टन एसिटिक एसिड, 19,000 टन फरफुरल और 31,000 टन खाद्य-ग्रेड CO_2।
- फीडस्टॉक: असम, अरुणाचल प्रदेश और अन्य पूर्वोत्तर राज्यों से 5 लाख टन बाँस प्राप्त किया जाएगा।
- आर्थिक प्रभाव: असम की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को ₹200 करोड़ का बढ़ावा, जिससे आदिवासी और बाँस उत्पादक समुदायों को लाभ होगा।

- प्रौद्योगिकी: नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड, फ़िनलैंड की फ़ोर्टम और केमपोलिस ओवाई का संयुक्त उद्यम; "शून्य-अपशिष्ट सुविधा"।

स्थैतिक संपर्क

- इथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम (ईबीपी): भारत का लक्ष्य 2025-26 तक 20% इथेनॉल मिश्रण करना है (2030 के लक्ष्य से आगे)।
- राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति 2018: गैर-खाद्य बायोमास (फसल अवशेष, बाँस, कृषि अपशिष्ट) से 2जी इथेनॉल को प्रोत्साहित करती है।
- ऊर्जा सुरक्षा: भारत लगभग 85% कच्चा तेल आयात करता है; जैव ईंधन आयात पर निर्भरता कम करते हैं।
- पर्यावरणीय लाभ: बायोएथेनॉल CO_2 उत्सर्जन को कम करता है और भारत के नेट ज़ीरो 2070 संकल्प का समर्थन करता है।
- जनजातीय आजीविका और बाँस: भारतीय वन अधिनियम में 2017 के संशोधन में बाँस को "घास" के रूप में पुनर्वर्गीकृत किया गया → अधिक मुक्त खेती और बिक्री।

सामाजिक-आर्थिक महत्व

1. ग्रामीण सशक्तिकरण: बाँस किसानों और जनजातीय समुदायों के लिए स्थिर आय प्रदान करता है।
2. औद्योगिक विकास: जैव-अर्थव्यवस्था और एसिटिक एसिड व फ़ुरफ़्यूरल जैसे मूल्यवर्धित उत्पादों को बढ़ावा देता है।
3. क्षेत्रीय विकास: पूर्वोत्तर भारत को ऊर्जा और जैव ईंधन केंद्र के रूप में स्थापित करता है।
4. आयात प्रतिस्थापन: कच्चे तेल के आयात बिल को कम करता है, जिससे विदेशी मुद्रा की बचत होती है।
5. स्थायित्व: शून्य-अपशिष्ट प्रौद्योगिकी पर्यावरणीय उत्तरदायित्व सुनिश्चित करती है।

चुनौतियाँ

- फीडस्टॉक आपूर्ति श्रृंखला: इतने बड़े पैमाने पर बाँस का स्थायी स्रोत महत्वपूर्ण है।
- परिवहन और भंडारण: पूर्वोत्तर भारत में बुनियादी ढाँचे की कमी।
- लागत प्रतिस्पर्धात्मकता: नीतिगत प्रोत्साहनों के बिना बायोएथेनॉल अक्सर जीवाश्म ईंधन से महँगा होता है।
- किसानों की भागीदारी: सुनिश्चित खरीद और उचित मूल्य निर्धारण की आवश्यकता है।
- प्रौद्योगिकी अपनाना: पूरे भारत में उन्नत जैव ईंधन संयंत्रों का विस्तार धीमा बना हुआ है।

निष्कर्ष

- गोलाघाट स्थित बाँस-आधारित इथेनॉल संयंत्र केवल एक ऊर्जा परियोजना नहीं है—यह एक सामाजिक-आर्थिक उत्प्रेरक है जो स्वच्छ ऊर्जा को जनजातीय सशक्तिकरण, क्षेत्रीय विकास और राष्ट्रीय ऊर्जा सुरक्षा से जोड़ता है। यदि ऐसी पहलों को दोहराया जाए, तो भारत अपनी ऊर्जा संबंधी त्रिविधियों: सामर्थ्य, स्थिरता और सुरक्षा को संतुलित करने में मदद कर सकता है, साथ ही अपनी जलवायु प्रतिबद्धताओं और ग्रामीण समृद्धि के लक्ष्यों को भी पूरा कर सकता है।

UPSC Prelims Practice Question

प्रश्न: भारत के पहले बांस-आधारित इथेनॉल संयंत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. इसका उद्घाटन असम के गोलाघाट जिले में किया गया है।

2. यह हरे बांस से इथेनॉल का उत्पादन करने वाला दुनिया का पहला शून्य-अपशिष्ट बायोइथेनॉल संयंत्र है।

3. यह परियोजना नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड और फिनलैंड की फोर्टम एंड केमपोलिस ओवाई के बीच एक संयुक्त उद्यम है।

4. संयंत्र अपने अंतिम उत्पादन के रूप में केवल इथेनॉल का उत्पादन करेगा।

कौन से कथन सही हैं**?**

a) केवल **1, 2** और **3**

b) केवल **1** और **4**

c) केवल **2, 3** और **4**

d) 1, 2, 3 और **4**

उत्तर: (**a)**

UPSC Mains Practice Question

प्रश्न: भारत के पहले बाँस-आधारित इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन ऊर्जा आत्मनिर्भरता, ग्रामीण सशक्तिकरण और सतत विकास की दिशा में एक कदम है। इस परियोजना के सामाजिक-आर्थिक और पर्यावरणीय महत्व पर चर्चा कीजिए, साथ ही ऐसी पहलों को आगे बढ़ाने में आने वाली चुनौतियों पर भी प्रकाश डालिए। **(150 Words)**

Page : 06 : GS 3 : Indian Economy / Prelims

आज़ादी के बाद से ही खाद्य सुरक्षा भारत के लिए एक प्रमुख चुनौती रही है। हरित क्रांति ने अनाज की पर्याप्तता सुनिश्चित की, लेकिन पोषण असुरक्षा अभी भी बनी हुई है। हाल ही में, एफएओ के मुख्य अर्थशास्त्री मैक्सिमो टोरेरो कुलेन ने इस बात पर प्रकाश डाला कि 40.4% भारतीय (लगभग 60 करोड़ लोग) स्वस्थ आहार (2024) का खर्च नहीं उठा सकते। हालाँकि 2021 (एसओएफआई रिपोर्ट) के 74.1% से इसमें काफ़ी सुधार हुआ है, फिर भी यह आँकड़ा गहरी पोषण असमानता को दर्शाता है।

India must invest more in accelerating diversification of food production: FAO Chief Economist Maximo Cullen

A.M. Jigeesh
NEW DELHI

About 40.4% of the Indian population (approximately 60 crore people) are unable to afford a healthy meal, says Maximo Torero Cullen, Chief Economist, Food and Agriculture Organization (FAO) of the United Nations.

Talking to *The Hindu*, Dr. Cullen said the number was a significant decrease from the FAO's assessment in 2023 that 74.1% of India's population was unable to afford a healthy diet in 2021.

He said India needed to start to invest more in accelerating the diversification of food production.

Dr. Cullen said India played a crucial role in achieving the Sustainable Development Goals of zero hunger by 2030 because of the level, size, and population of the country.

"Reduction of hunger in India affects the world and affects, of course, South Asia. So India, I think, has a huge role to play. That's why we believe it's so important that they continue and accelerate the transformation. India needs to move to the higher level – that is access to healthy diets, which right now is 40.4% of the population. So we need to improve that even more and also to find ways to assure this today and tomorrow," he said.

"The Green Revolution played its role, but now it's time to do more. So don't forget about it, but do more. We need to do more," Dr. Cullen said.

On the FAO's assessment in 2023 that 74.1% of India's population was unable to afford a healthy diet

Maximo Torero Cullen

in 2021, he said that in 2024, the percentage of the population that could not afford a healthy meal was 40.4.

"The methodology is improved. So yes, there is an important decrease. So the number to compare is basically to look at the State of Food Security and Nutrition in the World [SOFI] of this year to look at the previous year's number. But yes, there is a significant improvement, but still it's too high. Healthy diet is diversity. It means fruits and vegetables, proteins, and also means cereals. More than 40% of the country's population cannot afford a healthy diet. So it's a minimum cost to healthy diet," the FAO Chief Economist said.

Address the situation

Dr. Cullen added that the immediate step the Indian government should take to address the situation was diversification.

"India needs to start to invest more in accelerating the diversification of production. To move from cereals to high-value commodities. Pulses could be an option because they are more nutritious, they also have proteins. So pulses is an option and this is very consistent with your culture. But India should move more to fruits and vegetables and that requires an effort because you will need to substitute at some point," he said.

Tariff war

On the tariff war, he said the first problem of tariffs was inefficiencies.

"You will be more inefficient in the way you move commodities. Because before you were optimising the world, now the world is segmented. The world that wants low tariffs, but the world that has now high tariffs. The second issue is uncertainty. The changes of tariffs every day has created a lot of uncertainty and that complicates markets. Although markets have already learned how to manage this uncertainty, so things don't change too much," he said.

He, however, said the impact of food insecurity due to tariffs was not so high, but inefficiencies would be high.

"But assume they get into a situation where you play tit-for-tat, then this could be very dangerous. It's not happening at this point, countries are not responding. So let's see how it evolves, but uncertainty and inefficiencies will make us less resilient for sure, because we will have less places where to have food access because of the tariffs. It will affect farmers, it will affect the smallholders, especially will affect the farmers who are more linked to the markets. But what will happen at the end is that you will have a segmented trade," he said.

समसामयिक संदर्भ

- **एफएओ डेटा:**

  o 2021 – 74.1% आबादी स्वस्थ आहार का खर्च नहीं उठा सकती।

  o 2024 – घटकर 40.4% (पद्धतिगत सुधार + आर्थिक विकास)।

- स्वस्थ आहार की परिभाषा: अनाज, दालें, प्रोटीन, फल, सब्जियों का संतुलन।

एफएओ की सिफ़ारिश:

o अनाज से खाद्य उत्पादन में विविधता लाएँ → दालें, फल, सब्जियां।

o पोषण-संवेदनशील कृषि में निवेश करें।

o कैलोरी पर्याप्तता से आगे बढ़कर आहार विविधता की ओर बढ़ें।

स्थैतिक संबंध

- **भारत में खाद्य सुरक्षा**:

  o एनएफएसए 2013 लगभग 75% ग्रामीण और 50% शहरी आबादी को कवर करता है → अनाज तक पहुँच सुनिश्चित करता है, पूर्ण पोषण नहीं।

  o पीडीएस अभी भी काफी हद तक अनाज-केंद्रित (चावल, गेहूं) है।

  o आईसीडीएस और मध्याह्न भोजन योजनाओं का उद्देश्य पोषण है, लेकिन गुणवत्ता में कमी है।

- सतत विकास लक्ष्य: लक्ष्य 2 → 2030 तक भुखमरी को समाप्त करना।
- आर्थिक संदर्भ: 18-20% भारतीय अभी भी कुपोषित हैं (एफएओ अनुमान)।

मुख्य मुद्दे

1. अनाज-केंद्रित नीति: हरित क्रांति की सफलता ने गेहूँ और चावल पर ध्यान केंद्रित किया है।

2. पोषण अंतराल: दालें, फल, सब्जियाँ, पशु प्रोटीन अभी भी महँगे हैं → गरीबों के लिए वहनीय नहीं।

3. जलवायु तनाव: बढ़ते तापमान और अनियमित वर्षा पोषण-समृद्ध फसलों को प्रभावित करते हैं।

4. छोटे किसानों की भेद्यता: किसानों को विविधता लाने के लिए प्रोत्साहन का अभाव है; खरीद चावल/गेहूँ पर केंद्रित है।

5. व्यापार/शुल्क संबंधी मुद्दे: वैश्विक शुल्क युद्ध अकुशलता और अनिश्चितता को बढ़ाते हैं, जिससे खाद्यान्न की पहुँच और किसान प्रभावित होते हैं।

आगे की राह

- विविधीकरण: दालों, बाजरा (आईवाईएम 2023 गति), फलों और सब्जियों को प्रोत्साहित करें।
- सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार: केवल अनाज के बजाय धीरे-धीरे पोषक तत्वों की टोकरी की ओर बढ़ें।
- कृषि-निवेश: शीतगृह, भंडारण, नाशवान वस्तुओं का प्रसंस्करण।
- पोषण-संवेदनशील नीतियाँ: कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा (पोषण उद्यान, जैव-सुदृढ़ीकरण) को एकीकृत करें।
- अंतर्राष्ट्रीय सहयोग: टैरिफ झटकों से बचने के लिए स्थिर व्यापार व्यवस्था सुनिश्चित करें।
- स्थानीय समाधान: छोटे किसानों और आदिवासी समुदायों को विविध फसलें उगाने के लिए सशक्त बनाएँ।

निष्कर्ष

- भारत ने खाद्यान्न की पर्याप्तता हासिल कर ली है, लेकिन सच्ची खाद्य सुरक्षा का अर्थ है किफ़ायती, विविध और पौष्टिक आहार तक पहुँच सुनिश्चित करना। स्वस्थ भोजन का खर्च उठाने में असमर्थ 74.1% आबादी से घटकर 40.4% पर आना एक प्रगति है, लेकिन अभी भी संतोषजनक नहीं है। जैसा कि एफएओ रेखांकित करता है, अगली क्रांति एक "पोषण क्रांति" होनी चाहिए - मात्रा से गुणवत्ता की ओर, अनाज से विविधता की ओर बदलाव। ऐसा करके, भारत न केवल सतत विकास लक्ष्य-2 को प्राप्त कर सकता है, बल्कि कृषि को पोषण सुरक्षा से जोड़कर एक वैश्विक उदाहरण भी स्थापित कर सकता है।

UPSC Prelims Practice Question

प्रश्न: भारत में खाद्य सुरक्षा के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. एफएओ के **2024** के आकलन के अनुसार**,** भारत की लगभग **40.4%** आबादी स्वस्थ आहार का खर्च नहीं उठा सकती।

2. दालों को एक अच्छा विविधीकरण विकल्प माना जाता है क्योंकि वे प्रोटीन से भरपूर और भारत के लिए सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक हैं।

3. हरित क्रांति ने भारत में पूर्ण पोषण सुरक्षा सुनिश्चित की है।

4. एसडीजी-**2** (शून्य भूख) को प्राप्त करने के लिए फलों और सब्जियों की ओर कृषि का विविधीकरण आवश्यक है।

उपरोक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं**?**

a) केवल **1** और **2**

b) केवल **2** और **4**

c) केवल **1, 2** और **4**

d) 1, 2, 3 और **4**

उत्तर: **c)**

UPSC Mains Practice Question

प्रश्न: टैरिफ युद्ध और वैश्विक व्यापार अनिश्चितताएँ भारत की खाद्य सुरक्षा और छोटे किसानों को कैसे प्रभावित करती हैं**,** इसका परीक्षण कीजिए। कृषि व्यापार में लचीलापन लाने के लिए नीतिगत उपाय सुझाइए। **(150 Words)**

Page 09 : GS 2 : Social Justice / Prelims

- भारत उच्च शिक्षा के क्षेत्र में एक परिवर्तनकारी चरण में प्रवेश कर चुका है, जहाँ शीर्ष विदेशी विश्वविद्यालय यूजीसी के 2023 के नियमों के तहत भारत में अपने परिसर स्थापित कर रहे हैं। ब्रिटेन के एक विश्वविद्यालय ने गुरुग्राम (2025-26 सत्र) में अपना संचालन शुरू कर दिया है, और बेंगलुरु, चेन्नई, मुंबई और एनसीआर में भी जल्द ही नए परिसर स्थापित किए जाएँगे। यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 के उस दृष्टिकोण को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है जिसके तहत भारतीय उच्च शिक्षा को स्थानीय स्तर पर आधारित रहते हुए वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाया जाएगा।

वर्तमान संदर्भ

- नीतिगत सुधार: यूजीसी (2023) ने शीर्ष विदेशी विश्वविद्यालयों को परिचालन स्वायत्तता और नियामक स्पष्टता के साथ परिसर स्थापित करने की अनुमति दी।
- कार्यान्वयन: 12 आशय पत्र (एलओआई) जारी किए गए; एक परिसर पहले ही चालू हो चुका है।
- माँग कारक: बढ़ते आकांक्षी युवा, भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था और नए युग के क्षेत्रों (एआई, डिज़ाइन, डेटा विज्ञान, स्थिरता) की मांग।
- संस्थागत पारिस्थितिकी तंत्र: बहु-विषयक पाठ्यक्रम, अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन (अनुसंधान निधि), डिजिटल अवसंरचना और परिणाम-आधारित मान्यता जैसे सुधार।

स्थैतिक संबंध

- राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020: शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीयकरण और शैक्षणिक सहयोग का आह्वान।
- ऐतिहासिक भूमिका: भारत एक वैश्विक ज्ञान केंद्र रहा है (नालंदा, तक्षशिला, शांतिनिकेतन)।
- प्रतिभा पलायन की समस्या: भारत प्रतिवर्ष 13-15 लाख छात्रों को

Bringing global education home

Mamidala Jagadesh Kumar

is former Chairman, University Grants Commission, and former Vice-Chancellor, Jawaharlal Nehru University

Based on the University Grants Commission's recommendations, the Ministry of Education has handed over twelve letters of intent to top foreign universities to establish their campuses in India during the last year. One U.K. university has already opened its doors in Gurugram, launching its programmes for the 2025-26 academic session, with the remaining universities setting up campuses in Bengaluru, Chennai, Mumbai and the National Capital Region. The fact that world-class universities are establishing their physical campuses in India shows our conscious policy realignment. It opens new opportunities for our students and expands educational horizons in ways we could hardly imagine a decade ago.

The beginning point for this development is a regulation introduced by the University Grants Commission (UGC) in 2023. The idea is to allow top-ranking foreign universities to establish campuses in India with operational autonomy and regulatory clarity. The UGC took this calibrated decision to align with the vision of the National Education Policy (NEP) 2020. At its core, NEP 2020 calls for re-imagining higher education to be globally competitive while remaining locally rooted. Facilitating the establishment of global university campuses in India constitutes a direct implementation of that objective.

Why now?

India stands at an inflexion point. With a large aspirational youth population, India has a rapidly expanding and stable economy. Our start-up economy ranks among the fastest-growing globally and is a crucible of global innovation. There is a demand for quality higher education, especially in new-age fields such as AI, design, data science, sustainability, and finance.

Foreign universities are not arriving on empty ground. They are coming into a country already undergoing serious educational reform. Multidisciplinarity is being actively built into the curriculum. We are adopting hybrid educational delivery mechanisms using digital public infrastructure. Research funding is being streamlined through the Anusandhan National Research Foundation. Quality assurance mechanisms are becoming more outcome-oriented due to the reforms in accreditation. Foreign universities see the potential. Many western institutions face diverse challenges, including rising operational costs, demographic changes, and expanding globally. Establishing campuses in countries with a high youth population and growing intellectual capital makes strategic sense. India offers both.

> Students who might not have considered international education due to economic or social constraints can make that possibility real now

Local advantage, global gains

For students in India, its long-term impact could be truly consequential. Access to international-quality education without the high costs of going abroad changes the game entirely. Families no longer have to stretch their finances or send their children halfway across the world. The benefits go beyond academic degrees. Students will have exposure to diverse peer networks, industry partnerships, and entrepreneurial ecosystems embedded within the country.

And here lies a critical point. Students who might not have considered international education due to economic or social constraints can make that possibility real now. From the parents' perspective, the appeal is straightforward. They want their children to have the best possible education, and they want to feel secure in that choice. Sending a child abroad involves logistical, emotional, and financial complications. With global campuses coming to Indian cities, that equation changes.

This situation, in turn, raises the bar for Indian institutions as well. Healthy competition never hurts a system. When foreign university campuses in India offer cutting-edge programmes, our universities must innovate, reflect, and re-energise their models. There is a strong case for research collaboration, too. For instance, we have seen IITs, IISERs, AIIMS, central universities, and State universities collaborate with global partners on areas such as renewable energy, public health, and engineering. Australian and U.K. universities share strong educational collaborations with Indian universities. European and U.S. universities are intensifying linkages. These collaborations support research, innovation, and skills development.

Education powerhouse

India is a rising power in technology, diplomacy, and manufacturing. Yet, we rarely speak of our potential in global education with the same conviction. India must position itself as an emerging force in international education not by imitating the western university model, but by drawing the world to engage with us on our terms, within our cultural, intellectual, and societal landscape. India's centuries-old tradition of scholarship, from Nalanda to Shantiniketan, should not be seen as relics of the past, but as living sources of credibility in shaping a distinctive, modern learning environment. India already draws thousands of international students each year, yet the scale is negligible compared to our potential. Some claim that prioritising global education is a distraction from India's domestic needs. The truth is the opposite. Inviting the world's students, researchers, and institutions to work with us here also lifts our universities' quality, resources, and ambitions. To ignore this is to allow other nations to monopolise the narrative of what "world-class education" means, while we remain consumers instead of shapers of that narrative.

The views expressed are personal

विदेश भेजता है, जिससे लगभग 30-40 अरब डॉलर विदेशी मुद्रा का बहिर्वाह होता है। स्थानीय परिसर इस बहिर्वाह को कम कर सकते हैं।

- सॉफ्ट पावर: शिक्षा कूटनीति के एक उपकरण के रूप में, भारत के वैश्विक प्रभाव को बढ़ाती है।

सामाजिक-आर्थिक महत्व

1. सुगम्यता: छात्रों को विदेश जाने की उच्च लागत के बिना विश्व स्तरीय शिक्षा मिलती है।

2. समानता: मध्यम वर्ग और सामाजिक रूप से विवश परिवारों के लिए दरवाजे खोलती है जो विदेशी शिक्षा का खर्च वहन नहीं कर सकते।

3. प्रतिस्पर्धा और गुणवत्ता: भारतीय विश्वविद्यालयों के लिए नवाचार और आधुनिकीकरण के मानक को ऊँचा करता है।

4. अनुसंधान सहयोग: नवीकरणीय ऊर्जा, जन स्वास्थ्य, इंजीनियरिंग, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) में संयुक्त अनुसंधान की संभावनाएँ।

5. आर्थिक मूल्य: स्थानीय उद्योग संबंधों को बढ़ावा देता है, रोज़गार सृजन करता है और भारत की ज्ञान अर्थव्यवस्था को मज़बूत करता है।

6. वैश्विक स्थिति: भारत को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा के केंद्र के रूप में उभरने में मदद करता है, तकनीक और विनिर्माण क्षेत्र में इसकी बढ़ती स्थिति को और मज़बूत करता है।

चुनौतियाँ

- समान अवसर: भारतीय संस्थानों को संसाधनों और ब्रांड अपील के मामले में विदेशी विश्वविद्यालयों से प्रतिस्पर्धा करने में कठिनाई हो सकती है।
- सामर्थ्य: भारत में भी, विदेशी परिसरों की फीस ऊँची रह सकती है, जिससे समावेशिता सीमित हो सकती है।
- नियामक स्पष्टता: शोषण रहित शैक्षणिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए मज़बूत सुरक्षा उपायों की आवश्यकता।
- घरेलू प्राथमिकताएँ: बुनियादी ढाँचे और संकाय की कमी का सामना कर रहे भारत के विशाल राज्य विश्वविद्यालयों में शिक्षा के वैश्वीकरण और तत्काल सुधारों के बीच संतुलन बनाना।

निष्कर्ष

- भारत में विदेशी विश्वविद्यालयों का आगमन उच्च शिक्षा नीति में एक क्रांतिकारी बदलाव का प्रतिनिधित्व करता है—वैश्विक शिक्षा के उपभोक्ता से लेकर उसे आकार देने वाले बनने तक। हालाँकि सामर्थ्य, समानता और नियामक संतुलन की चुनौतियाँ अभी भी बनी हुई हैं, यह कदम प्रतिभा पलायन को कम कर सकता है, नवाचार को बढ़ावा दे सकता है और भारत को वैश्विक ज्ञान नेटवर्क में एकीकृत कर सकता है। यदि इसे भारत के सभ्यतागत लोकाचार और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के लक्ष्यों के साथ जोड़ा जाए, तो यह पहल भारत को न केवल एक आर्थिक महाशक्ति के रूप में, बल्कि 21वीं सदी के लिए एक वैश्विक शिक्षा केंद्र के रूप में भी स्थापित करने में मदद कर सकती है।

UPSC Prelims Practice Question
प्रश्न: भारत में विदेशी विश्वविद्यालय परिसर स्थापित करने की हालिया पहल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: **1.** यह विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के **2023** के नियमों के अंतर्गत सक्षम है। **2.** यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) **2020** के उद्देश्यों के अनुरूप है। **3.** विदेशी विश्वविद्यालयों को पूर्ण परिचालन स्वायत्तता होगी। **4.** केवल जी-**20** देशों के विश्वविद्यालयों को ही भारत में परिसर खोलने की अनुमति है। कौन से कथन सही हैं**?** **a)** केवल **1, 2** और **3** **b)** केवल **1, 2** और **4** **c)** केवल **2** और **3** **d)** केवल **1, 3** और **4** उत्तर: **a)**

UPSC Mains Practice Question
प्रश्न: शीर्ष विदेशी विश्वविद्यालयों को भारत में परिसर स्थापित करने की अनुमति देने से भारतीय उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए अवसर तो पैदा हो सकते हैं, लेकिन चुनौतियाँ भी पैदा हो सकती हैं। आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। **(150 Words)**

Page 10 : GS 3 : Science and Technology / Prelims

कट्टावेल्लई देवकर बनाम तमिलनाडु राज्य (2025) मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने आपराधिक मामलों में डीएनए नमूनों के प्रबंधन के लिए एक समान दिशानिर्देश जारी किए हैं। यह हस्तक्षेप तब किया गया जब न्यायालय ने हिरासत श्रृंखला में खामियों और नमूनों को फोरेंसिक विश्लेषण के लिए भेजने में अस्पष्टीकृत देरी पर ध्यान दिया, जिससे संदूषण और विश्वसनीयता पर संदेह पैदा हो रहा था।

What do SC guidelines say on DNA?

Why did the Supreme Court intervene in DNA samples in criminal cases? What lapses did the court uncover? What has the court said about DNA reliability in past rulings? What do the new guidelines mandate? Is DNA alone enough to convict?

EXPLAINER

R.K.Vij

The story so far:

The Supreme Court, in *Kattavellai @ Devakar v. State of Tamil Nadu*, recently issued guidelines to maintain the integrity of deoxyribonucleic acid (DNA) samples in criminal cases. The court directed the Director Generals of Police of all States to prepare sample forms of the Chain of Custody Register and all other necessary documentation as directed, and to ensure their dispatch to all districts with instructions.

What was the need to issue such directions?

The court, in the above case involving rape, murder, and robbery with an attempt to cause death, found significant unexplained delays in sending samples of the vaginal swabs to the Forensic Science Laboratory (FSL) for DNA analysis. Moreover, the chain of custody of the sample could not be established. Under such circumstances, the court held that the possibility of sample contamination could not be ruled out.

The court observed that although some guidelines have been issued by various bodies, there is neither uniformity nor a common procedure required to be followed by all investigating authorities. Even though 'Police' and 'Public Order' are subjects mentioned in the State List of the Seventh Schedule of the Constitution, the Supreme Court deemed it necessary to issue these guidelines to have uniformity of procedure.

What are the guidelines?

The Supreme Court issued four guidelines for cases where DNA evidence is involved. The first guideline states that the collection of DNA samples once made after due care and swift and appropriate packaging, including FIR number and date, the sections and statutes involved, details of the investigating officer, the police station, and the requisite serial number, shall be duly documented. The document recording the collection must include the signatures and designations of the medical professional present, the investigating officer, and independent witnesses.

Second, the investigating officer shall be responsible for the transportation of the DNA evidence (sample) to the concerned police station or hospital, as the case may be. He must also ensure that the samples reach the concerned FSL within 48 hours of collection. In the event of any delay, the reasons must be recorded, and all efforts should be made to preserve the samples.

Third, while samples are stored pending trial or appeal, no package shall be opened, altered, or resealed without express authorisation from the trial court.

The fourth guideline states that from the time of collection to the logical end, i.e., conviction or acquittal of the accused, a Chain of Custody Register must be maintained. This register must be appended to the trial court record. The investigating officer is responsible for explaining any lapses in compliance.

DNA is a molecule that encodes the genetic information in all living organisms. GETTY IMAGES

What has the Supreme Court said so far?

The DNA profiles have a tremendous impact on criminal investigations. In *Anil v. State of Maharashtra* (2014), the Supreme Court observed that a DNA profile is valid and reliable, but this depends on quality control and procedure in the laboratory. However, in the *Devakar* case, the court said that quality control and procedure outside the laboratory are equally important to ensure that the best results can be derived from collected samples.

In a three-judge Bench decision in *Manoj and Ors. v. State of Madhya Pradesh* (2022), the Supreme Court rejected a DNA report on the ground that recovery was made 'from an open area and the likelihood of its contamination cannot be ruled out'. It was also observed that the blood stains found on the articles were disintegrated, and the quantity was insufficient to run any classification test.

In another case, *Rahul v. State of Delhi, Ministry of Home Affairs* (2022), DNA evidence was 'rejected because it remained in the police Malkhana for two months and during such time, the possibility of tampering could not be ruled out'. It was said that 'the collection and sealing of the samples sent for examination were not free from suspicion'. The court also said the trial court and the High Court did not examine the underlying basis of the findings in the DNA reports or whether the techniques used had been reliably applied by the concerned expert.

Therefore, while the investigating agency needs to ensure that samples are collected properly, without any possibility of contamination, and sent to the FSL without any (unexplained) delay, the expert must also ensure proper quality control and procedure in the FSL.

How important is the DNA evidence in criminal cases?

DNA is a molecule that encodes the genetic information in all living organisms. It can be obtained from biological materials, such as bone, blood, semen, saliva, hair, or skin. Generally, when the DNA profile of a sample found at a crime scene matches the DNA profile of a suspect, it can be concluded that both samples have the same biological origin. However, it is not substantive evidence in criminal cases.

The Supreme Court, in the *Devakar* case, stated that DNA evidence is in the nature of opinion evidence as envisaged under Section 45 of the Evidence Act (Section 39 of the Bharatiya Sakshya Adhiniyam, 2023), and like any other opinion evidence, its probative value varies from case to case. Therefore, DNA evidence must be proved scientifically and legally.

R.K. Vij is a former IPS officer

THE GIST

- The Supreme Court has issued uniform guidelines to ensure the integrity of DNA samples in criminal cases, directing strict documentation, swift transfer, and a clear chain of custody.
- Past rulings show that lapses in handling have led to DNA reports being rejected, making both proper collection and quality control essential.

हस्तक्षेप क्यों?

- इस मामले में, योनि स्वाब के नमूनों के विलंब और गलत तरीके से संचालन के कारण संदूषण की संभावना थी।
- सर्वोच्च न्यायालय ने पाया कि सभी राज्यों में एक समान प्रक्रिया नहीं है।
- चूँकि 'पुलिस' और 'लोक व्यवस्था' राज्य सूची में आते हैं, इसलिए प्रक्रियाएँ व्यापक रूप से भिन्न थीं।
- इसलिए न्यायालय ने डीएनए साक्ष्य की अखंडता सुनिश्चित करने के लिए सभी राज्यों के लिए मानक दिशानिर्देश अनिवार्य कर दिए।

सर्वोच्च न्यायालय के दिशानिर्देश (2025)

1. उचित दस्तावेज़ीकरण: डीएनए नमूना संग्रह को प्राथमिकी विवरण, संबंधित क़ानून, जाँच अधिकारी के विवरण और डॉक्टर, जाँच अधिकारी और स्वतंत्र गवाहों के हस्ताक्षरों के साथ पैक किया जाना चाहिए।

2. समय पर प्रेषण: नमूने 48 घंटों के भीतर एफएसएल तक पहुँचने चाहिए; देरी का कारण स्पष्ट किया जाना चाहिए और संरक्षण सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

3. भंडारण: ट्रायल कोर्ट की अनुमति के बिना किसी भी पैकेज को खोला या दोबारा सील नहीं किया जाएगा।

4. कस्टडी रजिस्टर की श्रृंखला: संग्रह से लेकर ट्रायल/अपील तक बनाए रखा जाना चाहिए और अदालती रिकॉर्ड में संलग्न किया जाना चाहिए। जाँच अधिकारी को चूक का औचित्य सिद्ध करना होगा।

डीएनए साक्ष्य पर न्यायिक स्थिति (स्थैतिक + केस लॉ)

- अनिल बनाम महाराष्ट्र राज्य (2014): डीएनए प्रोफ़ाइल विश्वसनीय है, लेकिन प्रयोगशालाओं में गुणवत्ता नियंत्रण महत्वपूर्ण है।
- मनोज बनाम मध्य प्रदेश राज्य (2022): डीएनए को अस्वीकार कर दिया गया क्योंकि यह खुले क्षेत्र से प्राप्त किया गया था, संदूषण का जोखिम अधिक था।
- राहुल बनाम दिल्ली राज्य (2022): डीएनए को नष्ट कर दिया गया क्योंकि नमूने 2 महीने तक पुलिस मालखाने में रहे → छेड़छाड़ का संदेह।
- देवकर मामला (2025): विश्वसनीयता केवल प्रयोगशाला प्रक्रिया पर ही नहीं, बल्कि प्रयोगशाला से पहले के संचालन पर भी निर्भर करती है।

डीएनए साक्ष्य का महत्व

- प्रकृति: साक्ष्य अधिनियम की धारा 45 (अब धारा 39, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023) के तहत डीएनए साक्ष्य एक राय साक्ष्य है।
- प्रमाणिक मूल्य: मूल प्रमाण नहीं; अन्य साक्ष्यों से इसकी पुष्टि होनी चाहिए।
- उपयोगिता: यौन अपराधों, हत्या, गुमशुदा व्यक्तियों, पितृत्व विवादों में एक शक्तिशाली उपकरण।
- सीमाएँ: संदूषण का जोखिम, हिरासत श्रृंखला में चूक, गलत व्याख्या।

चुनौतियाँ

- भारत में फोरेंसिक बुनियादी ढाँचे और प्रशिक्षित कर्मचारियों का अभाव।
- कम फोरेंसिक बजट (पुलिस व्यय का 1% से भी कम)।
- वैज्ञानिक साक्ष्यों के बजाय स्वीकारोक्ति और गवाहों पर अत्यधिक निर्भरता।
- नमूने भेजने में न्यायिक देरी, साक्ष्य के मूल्य को कम करती है।

निष्कर्ष

- डीएनए तकनीक एक दोधारी तलवार है: यह किसी आरोपी को अपराध से निर्णायक रूप से जोड़ सकती है, लेकिन गलत तरीके से इस्तेमाल करने पर यह अविश्वसनीय हो जाती है। सर्वोच्च न्यायालय के नए दिशानिर्देश भारतीय न्यायालयों में डीएनए साक्ष्य की अखंडता, एकरूपता और स्वीकार्यता को मज़बूत करते हैं। फिर भी, दोषसिद्धि के लिए केवल डीएनए पर्याप्त नहीं है—पुष्टि आवश्यक है। आगे बढ़ते हुए, भारत को फोरेंसिक अवसंरचना, प्रशिक्षण और प्रौद्योगिकी-संचालित पुलिसिंग में निवेश करना होगा, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि न्याय न केवल हो, बल्कि वैज्ञानिक रूप से न्याय होता दिखाई दे।

UPSC Prelims Practice Question

प्रश्न: भारत में डीएनए साक्ष्य के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत डीएनए साक्ष्य को मूल साक्ष्य माना जाता है।

2. सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया है कि डीएनए नमूने संग्रह के **48** घंटों के भीतर फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला (एफएसएल) में पहुँच जाने चाहिए।

3. मुकदमे के तार्किक अंत तक कस्टडी रजिस्टर की एक श्रृंखला बनाए रखी जानी चाहिए।

4. संग्रह के दौरान केवल उपस्थित चिकित्सा पेशेवर को ही डीएनए साक्ष्य दस्तावेज़ पर हस्ताक्षर करने की आवश्यकता होती है।

उपरोक्त में से कौन सा सही है**?**

a) केवल **1** और **2**

b) केवल **2** और **3**

c) केवल **2, 3** और **4**

d) 1, 2, 3 और **4**

उत्तर: **b)**

UPSC Mains Practice Question

प्रश्न: "भारत की पश्चिम एशिया नीति नैतिक सिद्धांतों और व्यावहारिक राजनीति के बीच संतुलन बनाने के एक नाजुक कार्य का प्रतिनिधित्व करती है।" इज़राइल-फिलिस्तीन संघर्ष के संदर्भ में आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। **(150 Words)**

Page : 08 Editorial Analysis

Positioning India in an unruly world

M.K. Narayanan

is a former Director, Intelligence Bureau, a former National Security Adviser, and a former Governor of West Bengal

An article, in *Foreign Affairs*, titled "India's Great Power Delusions - How New Delhi's Grand Strategy Thwarts Its Grand Ambitions" (July/August 2025), is creating a storm in the proverbial tea cup. The article's key point is that India had 'delusions' of grandeur, and about becoming a Great Power, and that this lacked substance. More to the point, the article talks disparagingly about India, stating that it stood nowhere in the race between China and the United States, as far as the Great Power sweepstakes are concerned.

Not unexpectedly, this has ruffled feathers, at a time when India had begun to believe that it was on the cusp of overcoming the 'middle income trap' and emerging into the category of a Big Power. This may be termed delusional by some, but India's belief in its future is not new and has strong foundations. What may be faulted is the writer's premise that India and China are on the cusp of a conflict, and that India would need the United States' assistance to counter Chinese aggression. Both India and China are civilisational powers, though they have adopted different paths to progress. Neither country is, however, ready for a round of conflict, notwithstanding the existence of certain border issues between them. However, given India's experience in 1962 and 1971, when the U.S. went out of its way to remove any doubts that India might have had about U.S. support, the former is not looking for its aid in any future conflict.

The tenor of this article would suggest that the U.S. currently thinks that it can wield the big stick of the 'tariff war' to compel India to fall in line with its wishes. Lost in translation, however, is that Donald Trump's America is unable to comprehend the fact that the more advanced civilisations of the east, such as India and China, are not thinking of war or conflict at this time. Recent events and the meetings in Tianjin confirm this, and further demonstrate that India and China, along with Russia, constitute a strong phalanx against those anxious to disrupt the current world order – at least as far as Asia is concerned.

A closer look at the India story

It may, nevertheless, be worth analysing whether India's Big Power ambitions are indeed out of sync with reality. Also, whether it is wrong for India to start believing that achieving Great Power status is within reach. The first mistake made by critics is that India has never made the claim that it was about to overtake China in the near future. Or that it was within striking distance of the U.S. The worst that India can be accused of is to start believing that it had indeed pulled well ahead of a pack of nations that had started with similar hopes, and that India had succeeded in overcoming the 'middle income trap' – reaching striking distance of their main objective.

> India's belief in its future is not new and has strong foundations, which the West should understand

The derisive tone adopted by the writer of the article does seem to reflect an element of outrage at India's claims to progress. There is, however, a great deal to be said in favour of India's growth story, and, even more so, in the manner in which it has been achieved, in sharp contrast to that of countries such as China.

The Americans cannot be faulted for not reading or understanding history since this is not in their DNA. But India's spectacular transformation, from a 'famine affected' nation, through the Green Revolution, to becoming an exporter of food grains is, perhaps, unrivalled in the history of modern or even ancient times. Economic progress, rather than accumulating military strength, was the sine qua non of India's existence during its early years of independence, and provided the backbone for future progress. Butter before guns was the motto.

Nevertheless, and throughout this period, India exercised a degree of moral authority – that most countries including the U.S. have seldom exercised – to emerge as a balancing factor in international relations. This has few, if any, equals in politics post the Second World War. It is India that coined and propagated a new philosophy in international relations, *viz.*, the concept of Non Alignment, at a time when the world was split into two rival and conflicting orthodoxies; it helped safeguard the identity and hopes of newer nations post 1945, that did not wish to be aligned with either of the two rival blocs headed by the U.S. and Russia, respectively. India often acted as an arbiter in conflicts at the time (such as the Korean War in the 1950s), gaining international acclaim.

In the eyes of the West

The U.S.-China 'bromance' in the 1970s – achieved through the mesmerising diplomacy of then U.S. Secretary of State, Henry Kissinger, and his friendship with China's Deng Xiaoping – which transformed the attitude of the U.S. and of the West to China's potential as a market, had the effect of diminishing India's importance in western eyes, especially that of the U.S. Simultaneously, India's close friendship with Russia proved to be an irritant, further cemented with the signing of the India-Soviet Treaty of 1971. The 1974 nuclear test in the Pokhran desert – 'Buddha is Smiling' – aggravated this situation further.

The imperious tone of the *Foreign Affairs* article betrays a lack of understanding about India's ability to manage contradictions of every kind. India's relations with the U.S. vastly improved since the turn of the century, reaching a high point following the India-U.S. Civil Nuclear Agreement in 2008. But this happened even as India-U.S. relations were still far from warm. Many irritants remain, the most nagging of them being India's reliance on Russian weapons, and, more recently, Russian oil, despite U.S. opposition.

This is despite India having more than made up for this by joining the Quad (Australia, India, Japan, the U.S.). Managing contradictions is among the key strengths that this country has derived from its civilisational past, which is little understood by countries in the West, specially those in the far West such as the U.S. The mandarins in the U.S. are, hence, unable to comprehend how India and China, despite being embroiled in a border dispute, can also be friends, as evidenced during the recent Shanghai Cooperation Organisation (SCO) Summit. Even more confusing for the West is the 'entente cordiale' between China, India and Russia, as demonstrated on this occasion.

Technological superiority is the driver

What is truly delusional, however, is the failure of the West to recognise the real impetus in world affairs today, which stems from the 'empires of the mind'. In this respect, the U.S. today has far fewer cards to deal. This is the age of the 'cybernated generation' and the digital fortress is being breached today by countries with evolved civilisations such as China, India, Japan and Vietnam.

Harvesting data is today the main weapon of choice – and this is very different from employing 'laser weapons'. Technological superiority is leading to new digital colonies, and the U.S. can at best, and only for now, claim a marginal advantage over countries such as India. India's intrinsic capacity in this area, meanwhile, shows strong and steady growth. Those like the writer of the Foreign Affairs article, who scoff at India's strength may, hence, have to repent at leisure.

Rather than casting stones at India, the U.S. and the West would do well to contemplate whether their current lead in critical technologies may soon prove illusory. As a new wave of technology 'geeks' storm and overturn the citadels of the past, and usher in a new world order, this is a real possibility. The West would also do well to realise that the 'Sherpas' that dominate Silicon Valley today, are mainly of Indian and Asian origin.

The U.S.'s lead of today is, thus, at best, ephemeral. India, for its part, is betting on this leap of faith as far as technologies of the future are concerned, and the West would do well to understand them rather than depend on hackneyed themes of countries seeking U.S. support to protect themselves. The sun may well set on the U.S., and much earlier than it realises, even as an India, steeped in the virtues of an ancient civilisation and based on knowledge derived from centuries of civilisational existence, gains ground. Better positioning is more important today rather than indulging in vague concerns.

GS. Paper 02 – अंतरराष्ट्रीय संबंध

UPSC Mains Practice Question: भारत की अपनी विदेश नीति में विरोधाभासों को प्रबंधित करने की क्षमता उसके सभ्यतागत अतीत में निहित है।" प्रमुख शक्तियों के बीच भारत की संतुलनकारी भूमिका के संदर्भ में चर्चा कीजिए। (150 Words)

संदर्भ:

- विदेश मामलों में हाल ही में प्रकाशित "भारत की महाशक्तियों के भ्रम" (जुलाई-अगस्त 2025) शीर्षक वाले एक लेख ने भारत की व्यापक रणनीति और वैश्विक शक्ति के रूप में उभरने की क्षमता पर सवाल उठाकर बहस छेड़ दी है। आलोचकों का दावा है कि भारत अमेरिका और चीन से बहुत पीछे है, जबकि भारतीय विश्लेषकों का तर्क है कि ऐसे विचार भारत की सभ्यतागत लचीलापन, रणनीतिक स्वायत्तता और बढ़ती तकनीकी एवं आर्थिक क्षमताओं को कम आंकते हैं। यह बहस इस बात की जाँच करने का एक नज़रिया प्रदान करती है कि भारत एक अशांत वैश्विक व्यवस्था में खुद को कैसे स्थापित करता है।

स्थिर आयाम: भारत की महाशक्ति बनने की खोज

- सभ्यतागत विरासत: भारत ने ऐतिहासिक रूप से गुटनिरपेक्षता, शांति कूटनीति (जैसे, कोरियाई युद्ध में मध्यस्थता) और वैश्विक दक्षिण की वकालत के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में नैतिक अधिकार का प्रयोग किया है।
- सामरिक स्वायत्तता: स्वतंत्रता के बाद से, भारत ने महाशक्तियों के साथ गठबंधन का विरोध किया है, इसके बजाय एक बहु-वेक्टर विदेश नीति अपनाई है।
- आर्थिक आधार: भारत ने शुरुआती दशकों में "बंदूक से पहले मक्खन" को प्राथमिकता दी, खाद्य सुरक्षा (हरित क्रांति) और सैन्यीकरण की तुलना में औद्योगीकरण पर ज़ोर दिया।

वर्तमान संदर्भ: भारत की वैश्विक स्थिति

- आर्थिक विकास: "मध्यम आय के जाल" से उबरते हुए, दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर।
- रणनीतिक भूमिका: क्वाड, ब्रिक्स+, एससीओ का सदस्य; अमेरिका, रूस और चीन के साथ संबंधों को एक साथ संतुलित करना।
- ऊर्जा और रक्षा: अमेरिका की नाराज़गी के बावजूद, भारत रूस से रक्षा आयात और तेल खरीद को बनाए रखता है, जो स्वायत्तता को रेखांकित करता है।
- तकनीकी क्षेत्र: भारत डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, साइबर क्षमताओं और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में निवेश कर रहा है - जो भविष्य की शक्ति के महत्वपूर्ण चालक हैं।
- भू-राजनीतिक संतुलन: चीन के साथ सीमा विवादों के बावजूद, भारत एससीओ जैसे मंचों में भाग लेता है, साथ ही अमेरिका के नेतृत्व वाले सुरक्षा समूहों के साथ भी तालमेल बिठाता है।

आलोचकों द्वारा उजागर चुनौतियाँ

1. सैन्य विषमता: भारत का रक्षा खर्च और सैन्य क्षमताएँ चीन और अमेरिका से पीछे हैं।

2. आयात पर निर्भरता: रूसी हथियारों और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं पर भारी निर्भरता।

3. भू-राजनीतिक भेद्यता: चीन के साथ सीमा तनाव; अस्थिर पड़ोस (पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान)।

4. धारणा का अंतर: पश्चिमी विद्वान अक्सर भारत के सभ्यतागत दृष्टिकोण को "संकोची" या "भ्रमपूर्ण" समझ लेते हैं।

स्थिति निर्धारण में भारत की ताकतें

- विरोधाभासों का प्रबंधन: अमेरिकी साझेदारी और रूसी संबंधों के बीच संतुलन बनाने और ज़रूरत पड़ने पर चीन के साथ जुड़ने की क्षमता।
- सभ्यतागत गहराई: भारत वैश्विक सॉफ्ट पावर के लिए इतिहास, संस्कृति और कूटनीति का लाभ उठाता है।
- प्रौद्योगिकी और ज्ञान अर्थव्यवस्था: सिलिकॉन वैली के इंजीनियरों से लेकर स्वदेशी डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म तक, भारत एक "ज्ञान शक्ति" के रूप में उभर रहा है।
- वैश्विक दक्षिण नेतृत्व: संयुक्त राष्ट्र, विश्व व्यापार संगठन और जलवायु वार्ता में सुधारों का समर्थन; विकासशील देशों की आवाज़ के रूप में देखा जाता है।

निष्कर्ष

- महाशक्ति का दर्जा पाने का भारत का दावा महत्वाकांक्षी लग सकता है, लेकिन यह भ्रमपूर्ण नहीं है। चीन के राज्य-संचालित उदय या अमेरिका के सैन्य-औद्योगिक प्रभुत्व के विपरीत, भारत का उत्थान सभ्यतागत लचीलेपन, रणनीतिक स्वायत्तता और प्रौद्योगिकी-संचालित विकास पर आधारित है। सत्ता परिवर्तन और अनिश्चितता से ग्रस्त एक अशांत विश्व में, भारत की ताकत बहुध्रुवीयता को आकार देते हुए विरोधाभासों को संतुलित करने में निहित है। पश्चिमी आख्यानों को खारिज करने के बजाय, भारत को नैतिक अधिकार के साथ एक ज्ञान और प्रौद्योगिकी शक्ति के रूप में अपनी स्थिति बनाए रखनी चाहिए, और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसका उदय समावेशी, टिकाऊ और विशिष्ट रूप से भारतीय हो।

NITIN SIR CLASSES
NITIN SIR CLASSES
STARING 4TH OCT 2025
प्रारम्भ बैच (PT BATCH 2026)
DURATION : 7 MONTH
DAILY CLASSES : 2 (90 MIN EACH)
BOOKS - PT ORIENTED PYQ'S
MAGZINE : HARD + SOFT COPY
TEST SERIES WITH DISCUSSION
DAILY THE HINDU ANALYSIS
MENTORSHIP (PERSONALISED)
BILINGUAL CLASSES
DOUBT SESSIONS
ONE TIME PAYMENT
RS 17,500/-
PAY IN 2 EASY INSTALMENTS
RS 20,000/-
Register Now
https://t.me/NITIN KUMAR (PSIR)
99991 54587

NITIN SIR CLASSES
NITIN SIR CLASSES
STARING 4TH OCT 2025
आधार बैच (Aadhaar Batch)
DURATION : 2 YEARS
DAILY CLASSES : 2 (90 MIN EACH)
BOOKS - PT ORIENTED PYQ'S + MAINS
MAGZINE : HARD + SOFT COPY
NCERT FOUNDATION
SEPERATE PT & MAINS QUESTION SOLVING CLASSES
TEST SERIES WITH DISCUSSION
MENTORSHIP (PERSONALISED)
BILINGUAL CLASSES & DOUBT SESSIONS
MAINS ANSWER WRITING CLASSES
ONE TIME PAYMENT
RS 50,000/-
PAY IN 2 EASY INSTALMENTS
RS 55,000/-
Register Now
https://t.me/NITIN KUMAR (PSIR)
99991 54587

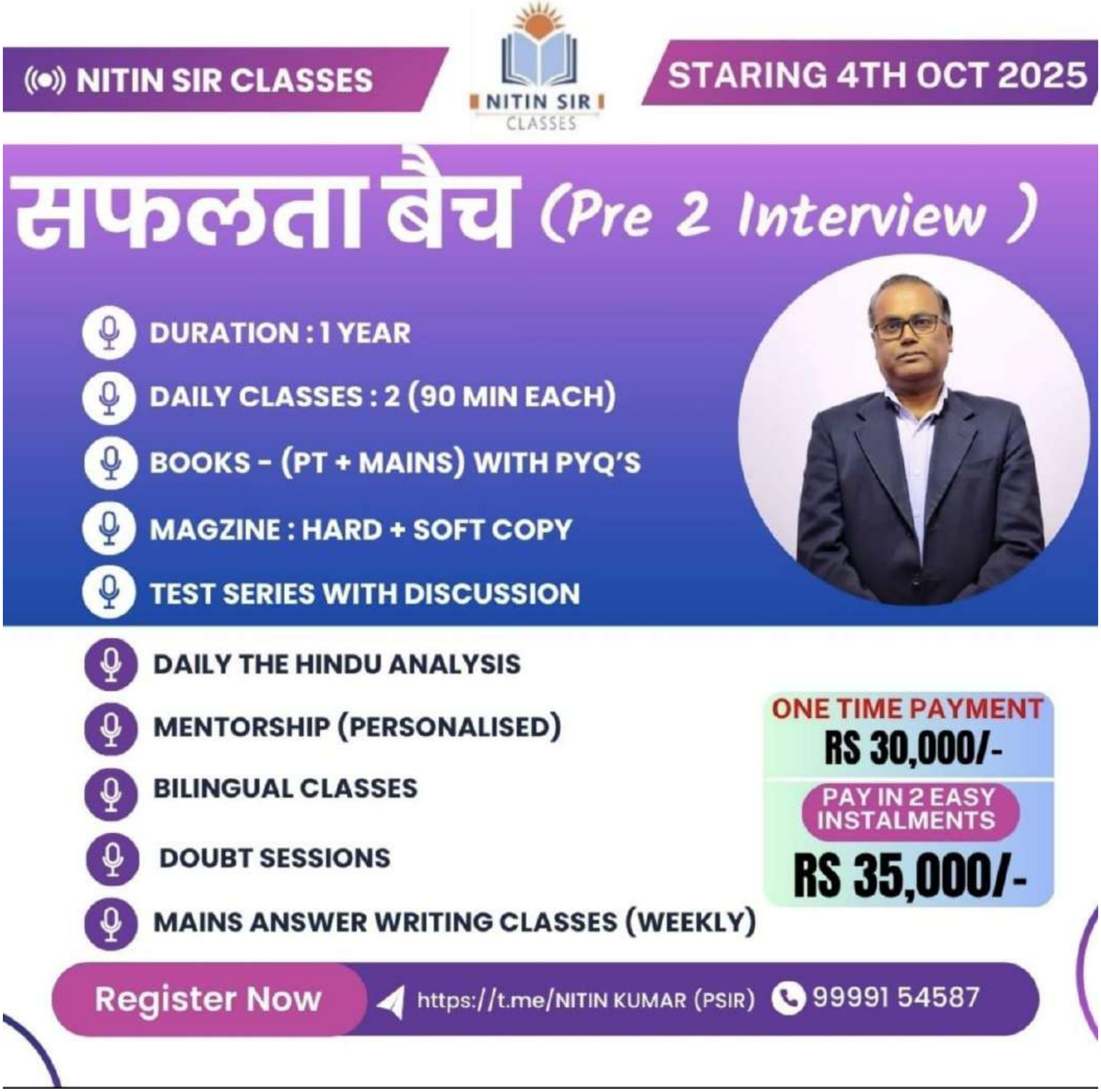
NITIN SIR CLASSES
NITIN SIR CLASSES
STARING 4TH OCT 2025
सफलता बैच (Pre 2 Interview)
DURATION : 1 YEAR
DAILY CLASSES : 2 (90 MIN EACH)
BOOKS - (PT + MAINS) WITH PYQ'S
MAGZINE : HARD + SOFT COPY
TEST SERIES WITH DISCUSSION
DAILY THE HINDU ANALYSIS
MENTORSHIP (PERSONALISED)
BILINGUAL CLASSES
DOUBT SESSIONS
MAINS ANSWER WRITING CLASSES (WEEKLY)
ONE TIME PAYMENT
RS 30,000/-
PAY IN 2 EASY INSTALMENTS
RS 35,000/-
Register Now
https://t.me/NITIN KUMAR (PSIR)
99991 54587

KNOW YOUR TEACHERS
Nitin sir Classes
HISTORY + ART AND CULTURE
GS PAPER I
ASSAY SIR
SHIVENDRA SINGH
SOCIETY + SOCIAL ISSUES
GS PAPER I
NITIN KUMAR SIR
SHABIR SIR
POLITY + GOVERNENCE + IR + SOCIAL JUSTICE
GS PAPER II
NITIN KUMAR SIR
GEOGRAPHY
GS PAPER I
NARENDRA SHARMA SIR
ABHISHEK MISHRA SIR
ANUJ SINGH SIR
ECONOMICS
SCI & TECH
GS PAPER III
SHARDA NAND SIR
ABHISHEK MISHRA SIR
INTERNAL SECURITY + ENG. (MAINS)
GS PAPER III
ARUN TOMAR SIR
ENVIRONMENT & ECOLOGY AND DISASTER MANAGEMENT
GS PAPER III
DHIPRAGYA DWIVEDI SIR
ABHISHEK MISHRA SIR
ETHICS AND APTITUDE + ESSAY + CURRENT AFFAIRS
GS PAPER IV
NITIN KUMAR SIR
CSAT
YOGESH SHARMA SIR
HISTORY
OPTIONAL
ASSAY SIR
SHIVENDRA SINGH
GEOGRAPHY
OPTIONAL
NARENDRA SHARMA SIR
ABHISHEK MISHRA SIR
PSIR + PUBLIC ADMINISTRATION
OPTIONAL
NITIN KUMAR SIR
SOCIOLOGY
OPTIONAL
SHABIR SIR
HINDI LITERATURE
OPTIONAL
PANKAJ PARMAR SIR
https://www.facebook.com/ nitinsirclasses
https://www.youtube.com/@nitinsirclasses8314
http://instagram.com/k.nitinca
https://t.me/NITIN KUMAR (PSIR)

Follow More

- **Phone Number : - 9999154587**
- **Website : - https://nitinsirclasses.com/**
- **Email : - k.nitinca@gmail.com**
- **Youtube : -https://youtube.com/@nitinsirclasses8314?si=a7Wf6zaTC5Px08Nf**
- **Instagram :- https://www.instagram.com/k.nitinca?igsh=MTVxeXgxNGJyajN3aw==**
- **Facebook : - https://www.facebook.com/share/19JbpGvTgM/?mibextid=qi2Omg**
- **Telegram : - https://t.me/+ebUFssPR83NhNmJl**